भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5464
25.03.2026 को उत्तर देने के लिए

एनएसओ द्वारा मॉडल-आधारित जिला-स्तरीय सामाजिक-आर्थिक प्राक्कलन

5464. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के लिए मॉडल-आधारित जिला-स्तरीय प्राक्कलन विकसित करने हेतु अध्ययन किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे जिला-स्तरीय प्राक्कलन किए जाने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली क्या है और सटीकता में सुधार लाने में सहायक डेटा स्रोतों की भूमिका क्या है;

(ग) इन सांख्यिकीय मॉडलों से साक्ष्य-आधारित और लक्षित स्थानीय विकास नियोजन में किस प्रकार सहायता मिलने की अपेक्षा है;

(घ) क्या सरकार का इस मॉडल आधारित प्राक्कलन पद्धति और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को अन्य राज्यों, विशेषकर त्रिपुरा राज्य में विस्तारित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के लिए गठित संचालन समिति ने संस्तुति किया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस): वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर मॉडल-आधारित जिला-स्तरीय अनुमान उत्पन्न करने की व्यवहार्यता पर एक प्रायोगिक अध्ययन करना चाहिए। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के जिला स्तरीय अनुमान उत्पन्न करने की संभावना का पता लगाने हेतु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), कोलकाता की पूर्व प्रोफेसर डॉ. मौसुमी बोस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, एनएसएस एवं डीईएस, उत्तर प्रदेश के सदस्य शामिल थे। समिति को मॉडल-आधारित तकनीकों, विशेष रूप से लघु क्षेत्र अनुमान (एसएई) विधियों का उपयोग करके उत्तर प्रदेश के जिलों हेतु एमपीसीई के आंकड़ों का अनुमान लगाने का दायित्व सौंपा गया।

(ख): उत्तर प्रदेश के जिलों हेतु एमपीसीई के विश्वसनीय अनुमान उत्पन्न करने हेतु, सह चर डेटा तथा निकटवर्ती जिलों से सामर्थ्य प्राप्त करने हेतु लघु क्षेत्र अनुमान अवसंरचना के तहत फे-हेरियट (एफएच) और स्पेशियल फे-हेरियट (एसएफएच) मॉडल को अपनाते हुए मॉडल-आधारित तकनीकों का उपयोग किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट (https://new.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports1761641209612_6875c53f-d8eb-4458-be3e-1e12a9e528c9_Compiled_Report_final17092025.pdf) पर उपलब्ध रिपोर्ट में विस्तृत अनुमान पद्धति के साथ-साथ इसके लाभ और समान परिस्थितियों में इसके उपयोग के मामलों का उल्लेख किया गया है।

(ग): समिति द्वारा अपनाई गई पद्धति का उपयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु उप-राज्य स्तर पर एमपीसीई मूल्यों का अनुमान तैयार किए गए हैं। क्रमश: एमपीसीई के ये अनुमान घरेलू आर्थिक स्थिति का अनुमान करने में सहायक होंगे, जिससे विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु नीतिगत निर्णय लेने में सुविधा होगी।

(घ) व (ङ): इस अध्ययन में अपनाई गई पद्धति को त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों और अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर भी लागू किया जा सकता है। राज्यों को आंकड़ों की कमी को दूर करने और जिला-स्तरीय अनुमान तैयार करने हेतु इसी तरह की पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां छोटे प्रतिदर्श आकार के कारण प्रत्यक्ष सर्वेक्षण अनुमान अशक्त हैं या उपलब्ध नहीं हैं।

*****